THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) Yes Sir, India has given notice for its withdrawal from International Jute Organisation (IJO), in April, 1998.

The step was taken as no consensus could be reached amongst IJO members for election of Indian candidate for the post of Executive Director, IJO, following pressure from the importing countries to get their candidate elected to the post. Moreover, it was felt that IJO has of late failed to live up to its main objectives and India as a major jute growing country stands to gain more from its own diversification and R&D Programme than from IJO.

Common Facility Centres for Handicrafts in Vidarbha

117. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a)whether Government have set up Common Facility Centres with modern machinery and equipments to tap the vast potential of handicrafts in the Vidarbha region of Maharashtra;

(b)if so, the details thereof; and

(c) if not, whether Government propose to set up such Common Facility Centres to promote handicrafts in Vidarbha region in the near future?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) No, Sir.

(b)Does not arise.

Presently, there is no proposal under consideration of the Government to set up such Common Facility Centre in Vidarbha region in the near future.

Revival of the National Textiles Corporation

118. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up any plan for the revival of the National Textiles Corporation;

(b)if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (c) On the basis of a unit-wise viability study made by NTC Government is considering a revised turn around strategy for the viable mills of NTC, keeping in view the BIFR norm of the net worth of these mills turning positive, within the period prescribed by BIFR.

पर्यटन का विकास और विस्तार

119. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या सरकार ने अगले दशक के दौरान देश में पर्यटन के विकास और विस्तार के लिए कोई अद्यतन योजना तैयार की है;

(ख) क्या पर्यटन उद्योग द्वारा अपेक्षित जिलों और राज्यों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या पर्यटन के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को निजी पर्यटन एजेंसियों तथा संगठनों के लिए खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या पर्यटन नीति का पुनर्विलोकन किया जायेगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) से (ग) देश में पर्यटन का विकास एंव विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है और आगामी दशक में पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है। इसमें सरंचना एवं उत्पाद विकास, मानव संसाधन विकास, संवर्धन एंव विपणन एवं मार्केट अनुसंधान सम्मिलित है। विकास की गतिविधियां राज्य सरकारों द्वारा हाथ में ली जाती हैं, और इन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता पर्यटन विभाग द्वारा, दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है। प्रवास यह है कि प्रत्येक राज्य में सभी पर्यटक केन्द्रों का केन्द्रीय एंव राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की सहायता से विकास हो। पर्यटन उद्योग मुख्यतया निजी क्षेत्र में हैं और सरकार की नीति आवश्यक सरलीकरण सेवाएं, प्रदा करके होटलों, रिजाटों और रेस्तराओं आदि जैसे पर्यटन संरचना लगाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की है।